

[Shri Kanwar Lal Gupta] here also, the Minister is supposed to clarify all these things, not only the allegation. That is my point.

MR. SPEAKER : It is only a suggestion and not a point of order. You kindly reply to the allegation.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I am sorry that I..

AN HON. MEMBER : made a statement

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : ...lost my temper for a minute while replying to my hon friend—he is an esteemed member of this House—Shri Shyamnandan Mishra. Obviously habits persist. But I would like to assure Mishraji and through you, the entire House that the Ministry of Home Affairs and the Ministry of External Affairs have been working in close co-operation on the question of impounding of pass ports. But my statement related to the liberalisation, not to issuing of pass ports. That is why I said... (Interruptions) There should be no misunderstanding on that score. Whatever has been published in the papers is not correct. There is perfect co-ordination between the two Ministries.

MR. SPEAKER : Shri Verma.

SHRI VAYALAR RAVI : On this I want a clarification.

MR. SPEAKER : No further clarification. I am not allowing... (Interruptions) I am not allowing any more clarifications. I have called Mr. Verma.

SHRI VAYALAR RAVI : I want a clarification on item No. 12.

In this very House Mr. George Fernandes when he was in charge of this Ministry made a policy statement. According to Constitution, Art. 75(3) it is the collective responsibility of the Ministry. When Mr. Fernandes made a statement of policy on the Communications Ministry on the floor of this House, we believed it was the policy of the government. Now, the Minister has changed. Here it is stated "some aspects" and not a change. You are within your right to change the policy. I am not questioning. Here, the order paper says "some aspects of the policy". It is not a new policy or a change in the policy but some aspects of the policy. My point is whether the government can change policies according to the change in the Ministers.

MR. SPEAKER : There is no point of order. It is always open to the government to change its policy.

12.40 hrs.

STATEMENT RE. SOME POLICY AND TELECOMMUNICATION SERVICES

संचार मन्त्री (श्री बृज लाल वर्मा) : मैं संचार मन्त्रालय को कार्य सम्बन्धी नीतियों में मोटे तौर पर जो कुछ तब्दीलियां करने की सोच रहा हूँ उनकी सूचना सदन को देना चाहता हूँ। अब देश में ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में दूरसंचार और डाक सुविधाओं के विकास पर और साथ साथ इन सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

अब तक की नीति के अन्तर्गत टेलीफोन और तार सुविधाएँ सभी जिलों सब-डिवीजनों तस्सीलों और ब्लाकों के सदर-मुकामों और उन जगहों में जिनकी आबादी 10,000 से अधिक है, दी जा रही थी। अब मैंने निर्देश दे दिया है कि ग्रामीण इलाकों में जिन जगहों की आबादी 5,000 या उससे अधिक हो और पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में जिन जगहों की आबादी 2500 और उससे अधिक हो उन जगहों में भी टेलीफोन और तार की सुविधाएँ देने की योजना बनाकर कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय। नई नीति के अनुसार इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए विभाग को होने वाली आमदनी का अन्दाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी जैसा कि पहले होता था। इस नीति से करीब 2000 हजार नए स्थानों में टेलीफोन के पी० सी० ओ० और तारघर खुल जायेंगे।

ग्रामीण इलाकों में ऐसी जगहों में भी जिनकी आबादी इससे कम हो टेलीफोन और तार की सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से मैंने हिदायत दी है कि उन जगहों में भी ये सुविधाएँ दी जाएं जहां सब-इन्स्पेक्टर के चार्ज वाला पुलिस थाना हो।

क्षेत्र जगहों में यह देखा जाएगा कि कामचयी कम से कम आसामा वर्ष की 25 प्रतिशत और पिछड़े इलाकों में कम से कम 15 प्रतिशत तथा पहाड़ी इलाकों में कम से कम 10 प्रतिशत हो। इस योजना के अन्तर्गत 1000 नई जगहों में टेलीफोन और तार की सेवाओं का विस्तार हो जाने की सम्भावना है।

इस प्रकार आशा है कि लगभग 4,000 नई जगहों में टेलीफोन और तार की सुविधाएँ दी जायेंगी। इनमें से 1,000 स्थान ऐसे हैं जहाँ पिछली नीति के अन्तर्गत ये सुविधाएँ दी जानी थी और 3,000 गांव ऐसे हैं जहाँ नई नीति के अन्तर्गत इन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बतलाया है, हमारा इरादा यह है कि अगले दो वर्षों में इन सभी जगहों में ये सुविधाएँ दे दी जाएँ। 2,000 स्थानों में चालू वर्ष में ही और शेष स्थानों में अगले वर्ष 1978-79 के दौरान, जो कि पाचवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होगा, टेलीफोन और तार की सुविधाएँ उपलब्ध करा दी जायेंगी। तुलना के तौर पर यह देखा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षों के कुल निम्नकर लगभग 2,600 स्थानों में ये सुविधाएँ दी गईं जबकि शेष दो वर्षों में 4,000 स्थानों में ये सुविधाएँ दी जायेंगी।

इस समय देश के 1 लाख 8 हजार से अधिक गावों में डाकघर काम कर रहे हैं। चालू वर्ष में हमने 3,100 गावों में नए डाकघर खोलने की योजना बनाई है इसके अतिरिक्त इसी वर्ष में चलते-चलते डाकघरों के जरिए 50,000 नए गावों में डाक काउंटर सुविधाएँ देने की योजना बना ली गई है। पोस्टमास्टर साइकिलों पर पड़ोस के गावों में जायेंगे और वहाँ डाकघर की सेवाएँ प्रदान करेंगे। इस योजना के पूरा होने पर इस वर्ष के अन्त तक 1 लाख 62 हजार से भी अधिक गावों में डाक लेखन सामग्री की बिम्बी और रजिस्ट्री, पार्सल और

मनीभांडर आदि की बुकिंग और वितरण जैसी डाक काउंटर सुविधाएँ उपलब्ध हो जायेंगी।

इस समय देश के 2 लाख गावों में लेटर-बक्स लगे हुए हैं। नई योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 1 लाख नए गावों में और लेटर-बक्स लगा देने का इरादा है।

आप जानते हो हैं कि इस वर्ष के अन्त तक देश के लगभग सभी गावों में दैनिक डाक वितरण योजना का विस्तार हो जाने की सम्भावना है।

इन सभी नई योजनाओं के पूरा हो जाने पर इस समय जितने गावों में डाक काउंटर सुविधाएँ और लेटर-बक्स सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उसके लगभग 50 प्रतिशत अधिक गावों में इन सुविधाओं का विस्तार इसी वर्ष हो जायेगा। आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक देश के सभी गावों में रोजाना डाक वितरण, 50 प्रतिशत से अधिक गावों में लेटर-बक्स और 25 प्रतिशत से अधिक गावों में डाक काउंटर की सुविधाएँ सुलभ हो जाएँगी।

टेलीफोन सलाहकार समितियों के गठन में निहित मुक्ति पर भी गहराई में विचार किया गया है। अब तक देश में केवल महारों के लिए 96 टेलीफोन सलाहकार समितियाँ बनी हुई थीं। अब मैंने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक राज्य और सभ शासित क्षेत्र के लिए अलग-अलग टेलीफोन सलाहकार समिति बनाई जाए, जो न केवल महारों के लिए बल्कि गावों सहित समूचे राज्य के टेलीफोन एक्सचेंजों और पी०सी०ओ० की टेलीफोन सेवाओं के संबंध में विभाग को सलाह दे। राज्यों की ऐसी टेलीफोन सलाहकार समितियों के अलावा उन बड़े महारों में भी जहाँ 10,000 से अधिक टेलीफोन फोन कर रहे हैं, अलग-अलग टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया जाएगा। अब

### [बी वूज लाल वर्मा]

प्रकार जब केवल 49 टेलीफोन सलाहकार समितिया होगी।

मैंने यह भी फँसला किबा है कि जब से कमेटी के अध्यक्ष और सचिव—जो सरकारी अधिकारी होते हैं—के अलावा इन टेलीफोन सलाहकार समितियों में अधिक से अधिक 21 सदस्य होंगे। इन उपायों से मैं आशा करता हूँ कि टेलीफोन सेवा को बेहतर बनाने और इसके लक्ष्य विस्तार के बारे में टेलीफोन उपभोक्ताओं और प्रशासन के बीच और वनिष्ठ तालमेल स्थापित होगा।

आशा है कि सितम्बर, 1977 तक इन समितियों का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। इनका कार्य-काल दो वर्ष होगा। इन टेलीफोन सलाहकार समितियों में सदस्य के राज्यों के विधान-मंडलों के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा।

टेलीफोन सलाहकार समितिया के ढांचे में होने वाले परिवर्तन का क्षेत्रीय डाक-तार सलाहकार समितियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे पहले की भांति ही कार्य करती रहेंगी।

उच्च स्तर की सेवा प्रदान करने के लिए सारे देश में फीले दूरसंचार यंत्रों और लाइनों को सामूहिक तौर पर सुगठित करने के कार्य को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

खास तौर पर बरसात में मौसम में टेलीफोनो की खराबियों की रोक थाम के लिये मुख्य नगरों में टेलीफोन के केबुलों को प्रेशराइज करने की एक विशेष योजना बनाई गई है। ऐसे नगरों के टेलीफोनो में लगभग 12,500 किलोमीटर हैं। पिछले तीन वर्षों में इनमें 3,000 किलोमीटर केबुल प्रेशराइज किये जा चुके हैं। शेष 9,500 किलोमीटर केबुल भी अगले दो वर्षों में अर्थात् 1979 में बरसात प्रारंभ होने से पहले प्रेशराइज कर देने की योजना बनाई गई है। इससे से करीब आधे केबुलों की

प्रेशराइज करने का कार्य 1978 में अर्थात् बरसात प्रारंभ होने से पहले पूरा हो जाने की संभावना है।

जेली-बरे हुए विशेष केबुलों का भी अधिक प्रयोग किया जाएगा। खास केबुलों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से मुख्य सड़कों के नीचे या महत्वपूर्ण सड़कों के किनारे, जिनके पक्के फर्श बनाए जा रहे हैं, पक्की बंद नालिया बनाने की योजना बनाई गई है ताकि इन केबुलों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचने से बचाया जा सके।

एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमें चाल वर्ष में एक्सचेंजों के साज-सामान की बारीकी से चैकिंग और ओवरहालिंग की जाएगी। पेटाकोष्टा फासबार एक्सचेंजों की सेवा में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल यह कार्य करेगा। उपभोक्ताओं के टेलीफोन यंत्रों और फिटिंगों की जाच के लिए भी एक अभियान चलाया जाएगा। आशा है कि इस वर्ष पूरे देश के करीब 50 प्रतिशत टेलीफोन यंत्रों और फिटिंगों की पूरी तरह जाच और ओवरहालिंग कर दी जाएगी और शेष कार्य अगले वर्ष पूरा कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों की एक टीम टेलीफोन इस्टीमेट और डायल की क्वालिटी की जाच कर रही है। यह समिति इनमें सुधार के उपाय बताएगी, जिससे कि ये यंत्र बगैर खराबी के अधिक से अधिक समय तक अच्छी सेवा दे सकें। चार बड़े टेलीफोन जिलों के सगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के लिए मैंने एक उच्चस्तरीय समिति बना दी है। उस समिति ने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है।

अपनी विदेश दूरसंचार सेवाओं के विस्तार और उनके आधुनिकीकरण (मार्ड-नाइवैशन) पर अधिक बल दिया जाएगा। हमारी यह योजना है कि इस वर्ष के

कांठ क्लब उन 39 बेचो मे से 36 बेचों के साथ जबके सहां हिंद महासागर इटेलसेट उपग्रह की ओर उन्मुख मानक भू-उपग्रह केन्द्र (स्टेडर्ड ग्रुप-स्टेशन) है, हम सीधी उपग्रह संचार सेवा स्थापित कर लें। अपनी यह योजना पूरी करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। सोवियत रूस के साथ सीधे ट्रोपोस्केटर सर्क स्थापित करने और मद्रास को मलेशिया के साथ जोड़ने वाले अन्त समुद्री (सब-मैरीन) केबुल की स्कीमे भी हाथ मे ले ली गई है। दिल्ली और बम्बई मे अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन और टेलिक्स सेवाओं के लिए आधुनिक गेट-वे एक्सचेंज बनाने की योजना बनाई गई है। देहरादून के भू-उपग्रह केन्द्र मे ऐसा उपस्कर लगाया गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारणो का संचालन करने मे सक्षम है। ये परियोजनाएँ पूरी होने पर भारत की विश्व दूर-संचार सेवाएँ विश्व के किसी भी उन्नत देश की ऐसी सेवाओं के मुकाबले की हो जाएगी।

**SHRI VAYALAR RAVI** Sir, I rise on a point of order

**MR. SPEAKER** He is on a point of order. What is your point of order?

**SHRI VAYALAR RAVI** My point of order is this. Just now the Minister said about the extension of the international subscriber dialing telephone service to the whole of U.K. Only a few days ago when the House is in session the hon. Minister made a press statement on the same subject—a week ago outside—and today he makes a policy statement. That is my point of order. He made a press statement last week.

**MR. SPEAKER** You could have raised the privilege question and not a point of order. You cannot raise a point of order that he cannot make his statement.

**SHRI K P UNNIKRISHNAN** (Badagara) He regards this as a privilege and so he reserves his right to move a privilege motion.

**MR. SPEAKER** That is a different matter. I have already ruled out his point of order.

**SHRI S. KUNDU** (Balevore); Sir, I rise on a point of order. My point of order is that when the hon. Members of the Opposition raise points of order, they should not threaten that they are going to bring a privilege motion. That is what I object to.

**MR. SPEAKER** I think the rules require to be changed. When the points of order are raised several Members should not raise them every day.

**PROF P G MAVALANKAR** (Gandhinagar) rose—

**MR. SPEAKER** Is it a point of order? Any other thing was not allowed.

**PROF P G MAVALANKAR** Kindly listen to me. When the hon. Minister was making a policy statement he had gone into other questions.

**MR. SPEAKER** That is not a point of order. You should have said it earlier.

**PROF P G MAVALANKAR** Sir, I am only making my submission. The hon. Minister, while making a statement has gone into the entire gamut of the working of the various departments in his Ministry last week. I would be brief, Sir. Last week while the Minister was replying to specific questions, you had permitted supplementaries.

**MR. SPEAKER** Under what rule you are making your submissions?

**PROF P G MAVALANKAR** Sir, I wrote to you seeking your permission before 10 o'clock. I took care to write a letter to you seeking permission earlier to speak.

**MR. SPEAKER** You cannot do that. Rule 372 does not provide for that. That is why, in this particular case, last time, a certain indulgence was given. And everybody had started making submissions. Hence, I am not allowing it now.

**PROF P G MAVALANKAR** Under Rule 377 I have a right.

**MR. SPEAKER** No please. The hon. Minister may continue now.

श्री कजलाल वर्मा इस समय बम्बई और लखन तथा नई दिल्ली और लखन के बीच अन्तर्राष्ट्रीय एस० टी० बी० (उपचोक्ता

### श्री बृजलाल वर्मा]

ट्रक डायलिंग) टेलीफोन सेवा दिन में कुछ समय के लिये उपलब्ध है। सितम्बर 1977 के अंत तक समूचे ब्रिटेन के लिये यह सेवा चौबीसो घंटे मिलने लगेगी। भाशा है कि मार्च 1978 तक ऐसी सेवा समस्त राज्य अमरीका के न्यूयार्क और वाशिंगटन नगरों के लिये भी चालू हो जायेगी।

मेरे मन्त्रालय के अधीन जो दूर संचार उपकरण का निर्माण करने वाली एग्जिटिभिवल डेवेलपमेंट्स एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और डाक तार कारखाने हैं, उन की वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का मैं इस दृष्टि से पुनरीक्षण कर रहा हूँ कि उन की उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ जाये कि वे देश की सभी आवश्यकताये पूरी कर सकें। मेरा यह प्रयत्न होगा कि अगले तीन चार वर्षों में दूरसंचार के उच्च कोटि के साज सामानों के उत्पादन में देश आत्मनिर्भर हो जाये।

जब से मैंने संचार मंत्री का कार्यभार सभाला हूँ, विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों और उन के सभी के प्रतिनिधियों के साथ मेरा अनिष्ट सम्पर्क होता रहा है। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि वे अधिक कुशल, विश्वसनीय और उच्चकोटि की सेवा प्रदान करने में अपना पूर्ण समर्थन देगे। विभाग के सभी कर्मचारियों के ऐसे बड़े हुए उत्साह और उन के पूर्ण सहयोग को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में हम सभी तरह से बेहतर सेवा प्रदान करने में सफल होंगे।

12 55 hrs.

### PERSONAL EXPLANATION BY MINISTER

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री  
(श्री राज नारायण) - आधारीय अग्र्यक्ष महोदय, बिनाक 4 अगस्त, 1977 को शोक

सभा में किन्दा प्रस्ताव पर बोसते समय श्री उन्नीकुण्डन ने यह मंत्री एच कैरे विरुद्ध व्यक्तिगत, अनर्गल एव असत्य आरोप लगाए थे उस विषय में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा।

डा० जे० पी० सिंह जो चौधरी साहब के दामाद हैं विलिंगडन अस्पताल में सर्जन हैं उन्होंने 24 मार्च, 1972 को श्री कटेश्वरनाथ के पेट का आपरेशन किया और उस आपरेशन के दौरान एक बैबकाफ फोसेप उनको असाध्य म रह गया जो 28 मार्च, 1972 को निकाल दिया गया। इस घटना के तुरन्त बाद 4 अप्रैल, 1972 को डा० एल० आर० पाठक जो उस समय विलिंगडन अस्पताल में सर्जरी विभाग के प्रधान थे और डा० डी० बी० बिष्ट जो उस समय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक थे, दोनों ने इस घटना के लिए डा० जे० पी० सिंह को बिल्कुल दोषी नहीं पाया। बाद में इन घटना के सबंध में लिए गये बयानों के आधार पर तत्कालीन महानिदेशक ने निम्नलिखित टिप्पणी की -

"Staff Nurse, Kunju Kutty, who relieved staff nurse, B Abraham, during the course of operation on Shri Kateshwar Nath at 1 35 p.m. has in her statement admitted that the surgeon at the time the operation ended had asked routinely if every count was O.K. and that she answered "Yes".

Staff Nurse Kutty is accordingly responsible for having missed to count the number of instrument which were available with her after the operation has ended

I consider that the responsibility for the mishap is of the nurses who assisted the surgeon in the operation."

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि डा० जे० पी० सिंह की इस असावधानी के लिए कोई जिम्मेदारी इन अधिकारियों ने अपनी पहली जांच में नहीं रखी। पत्रावली को देखने से ज्ञात होता है कि इस मामले की जांच के दौरान डा० एल० सी० नाटिया, जूनियर मेडिकल ऑफिसर, विलिंगडन अस्पताल, कुंजी